17वीं लोकसभा, 2019

सी पी आइ (एम) का चुनाव घोषणापत्र

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के शासन के पांच बरस, देश और जनता के लिए पूरी तरह से सत्यानाशी साबित हुए हैं।

इस बार का चुनाव, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। आज हमारे संविधान में समाविष्ट, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणतंत्र का ही भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह भविष्य इसलिए दांव पर लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भाजपा-नीत एनडीए सरकार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अभूतपूर्व तरीके से धारदार बनाने के लिए काम कर रही है। यह हमारे समृद्ध, विविधतापूर्ण सामाजिक ताने-बाने के सौहार्द्र को छिन्न-भिन्न किए दे रहा है। इन पांच सालों के दौरान इस सरकार ने तमाम संवैधानिक सत्ताओं तथा प्राधिकारों के खिलाफ, नंगा और मुसलसल हमला किया है। भाजपा अगर केंद्र सरकार की मु िया बनी रहती है तो यह हमारे संविधान के आधार स्तंभों को और भी कमजोर कर देगा।

इसलिए, इस चुनाव में भारतीय मतदाताओं के सामने सबसे पहला यह सुनिश्चित करना है कि यह सरकार हारे और एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना के पक्ष में जनादेश आए, जो हमारे संवैधानिक गणराज्य की हिफाजत करे और उसके बाद उसे पु ता करने के रास्ते पर आगे बढ़े। बहरहाल, यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है, जब मौजूदा नीतिगत दिशा को मूलगामी तरीके से जनता के पक्ष में बदला जाएगा। इसके लिए, 17वीं लोकसभा में सी पी आइ (एम) और वामपंथ की और प्रबल उपस्थिति होना जरूरी है।

जनतंत्र पर हमले

इन पांच सालों में सभी संवैधानिक संस्थाओं तथा प्राधिकारों पर और जनता के संविधान में गारंटीशुदा अधिकारों पर, भीषण तानाशाहाना हमला हुआ है।

कुछ उदाहरण:

संसद के काम-काज में गंभीर तरीके से कतर-ब्योंत की गयी है। सरकार की जवाबदेही संसद के प्रति है और सांसदों की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता द्वारा यानी जैसाकि हमारे संविधान का पहला वाक्य कहता है, हम भारत के लोगों द्वारा इसी तरह से अपनी संप्रभुता का व्यवहार किया जाता है।

मोदी सरकार ने उपरले सदन, राज्यसभा के स्वतंत्र काम-काज को कमजोर किया है। राज्यसभा को बाइपास करने के लिए ''मनी बिल'' के रास्ते का अंधाधुंध सहारा लिया गया है। संसदीय कमेटियों के काम-काज को, जो वास्तव में विधायी निगरानी का काम करती हैं, पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है।

न्यायपालिका के मामलों में नंगी दखलंदाजी, जनता को न्याय से वंचित कर रही है और जिन न्यायाधीशों के कंधों पर जनता को न्याय देने की तथा संविधान की हिफाजत करने की जि मेदारी है, उनके बीच ही असंतोष पैदा कर रही है।

जांच एजेंसी **सीबीआइ** की सर्वोच्चता को कमजोर किया गया है और प्रधानमंत्री तथा सरकार के राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्र नियमनकारी सत्ता को कमजोर किया गया है और सरकार के खर्च की भरपाई करने के लिए, रिजर्व बैंक के सुरक्षित फंड को हड़पने की कोशिशें की जा रही हैं।

मजदूर वर्ग, किसानों तथा मेहनतकश जनता के सभी तबकों के, अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर, विरोध कार्रवाइयां संगठित करने के **अधिकारों में काट-छांट** की जा रही है।

हरेक नागरिक के निजता के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के संविधान प्रदत्त अधिकार पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। मीडिया पर हमले हो रहे हैं और सरकार के प्रति आलोचनात्मक स्वर अपनाने वालों पर सोशल मीडिया में तथा अन्यत्र हमले हो रहे हैं। आरएसएस-भाजपा की आलोचना करने वालों को अंधाधुंध राष्ट्रविरोधी करार दिया जा रहा है। जनतांत्रिक असहमति को ही जुर्म बना दिया गया है। सरकार के निशाने पर आए तबकों, जैसे दालित आदि के पक्ष में खड़े होने वाले बुद्धिजीवियों तथा वकीलों को परेशान किया जाए जा रहा है तथा डराया-धमकाया जा रहा है।

आरएसएस-भाजपा के आलोचकों पर हिंसक शारीरिक हमले हो रहे हैं। यह सिलसिला डा0 नरेंद्र दाभोलकर, का0 गोविंद पानसरे, डा0 एम एम कलबुर्गी तथा गौरी लंकेश जैसे विवेकवादियों तथा बुद्धिजीवियों की हत्याओं तक जाता है।

धर्मनिरपेक्षता पर हमले

मंदिर निर्माण, मुस्लिम नामों को हटाते हुए सार्वजनिक जगहों के नामांतरण जैसे विवादी मुद्दों पर **सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ाया** जा रहा है। अल्पसं यकों को निशाना बनाकर, घृणा तथा हिंसा का वातावरण बनाया गया है।

गोरक्षा तथा नैतिक दारोगागीरी के नाम पर, **निजी सेनाओं** को संरक्षण दिया जा रहा है। दलितों तथा मुसलमानों पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। निजी सेनाओं की बेरोक-टोक गतिविधियों के चलते, भीड़ हिंसा/ हत्या की वारदातें हो रही हैं।

शिक्षा प्रणाली का हमलावर तरीके से सांप्रदायीकरण

नंगई से आरएसएस के अधिकारियों को सभी विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थाओं में, शोध संस्थाओं में, सांस्कृतिक अकादमियों आदि में, ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है, ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली का सांप्रदायीकरण किया जा सके।

वे सभी स्तरों पर **पाठ्यचर्या की अंतर्वस्तु** को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ा सकें।

सत्यानाशी आर्थिक नीतियां

इन पांच सालों में आर्थिक गतिविधि के एक-एक क्षेत्र के दरवाजे **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** के लिए खोले गए हैं और उनके अपने मुनाफे अधिकतम करने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बड़े पैमाने पर **निजीकरण** किया गया है और बेशकीमती सार्वजनिक परिसंपत्तियां छंटे हुए विदेशी तथा भारतीय कार्पोरेटों के हवाले की जा रही हैं।

दरबारी पूंजीवाद को बेरोक-टोक बढ़ावा दिया जा रहा है। रफाल घोटाला, चुनाव की पूर्व-संध्या में अडानी ग्रुप को निजी क्षेत्र में चलाने के लिए पांच घरेलू हवाई अड्डों का सौंपा जाना तथा भारत का पहला बिजली क्षेत्र का सेज सौंपा जाना, आदि इसी के सबूत हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदे पर पहले लगी रही सभी सीमाओं को हटाकर, चुनावी बांड की योजना शुरू की गयी है, जो इस तरह के दरबारी-रिश्ते से लाभ बटोरने के लिए ही लायी गयी है।

सार्वजनिक धन की लूट को सुगम बनाया जा रहा है तथा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका पता डूबंत ऋण 11 लाख करोड़ रु0 से ऊपर पहुंच जाने से चलता है।

नोटबंदी के जरिए, नकद लेन-देन से गुजारा करने वाले करोड़ों लोगों की आजीविकाओं को नष्ट कर दिया गया।

जीएसटी के लागू किए जाने के जरिए, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को करीब-करीब नष्ट ही कर दिया गया। खेती के बाद, सबसे ज्यादा रोजगार इन उद्योगों में ही मिलते हैं। मुद्रा ऋणों में डूबंत कर्जे, 2017-18 की तुलना में, 2018-19 के पहले नौ महीनों में ही 53 फीसद बढ़ गए।

जनता की आजीविका पर अभूतपूर्व हमले

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते खाद्यान्न की, मनरेगा के तहत मजदूरी आदि की जनता की हकदारियों को छीना गया है या उनमें भारी कटौतियां की गयी हैं।

गहराते कृषि संकट से तबाह होते भारतीय किसान और बढ़ती हताशा में आत्महत्याएं

देहात में जनता का जीना इतना मुश्किल पहले कभी नहीं था। ग्रामीण जनता की वास्तविक आय में अभूतपूर्व तरीके से गिरावट आयी है।

2018 की आखिरी तिमाही--अक्टूबर-दिसंबर--में कृषि आय वृद्धि गिरकर 14 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी और सिर्फ 2.67 फीसद रह गयी (केंद्रीय सांि यकी कार्यालय)। रिजर्व बैंक की रिपोर्टें बताती हैं कि कृषि के क्षेत्र में चुकाए न जा सके ऋण, जो 2017 के सितंबर में 70,000 करोड़ रु0 के थे, 2018 के सितंबर तक बढ़कर 1 लाख करोड़ रु0 पर पहुंच चुके थे। इतना भारी कृषि संकट ही हताशा में आत्महत्या करने वाले किसानों की सं या बढ़ा रहा है।

बेरोजगारी

पिछले कुछ सालों में रोजगार के अवसरों में तेजी से गिरावट आयी है, जिससे हमारे युवा कुंठित हो रहे हैं। मोदी ने हर साल, 2 करोड़ नयी नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। उसे अब तक 10 करोड़ नये रोजगार पैदा करने चाहिए थे। लेकिन, सचाई यह है कि बेरोजगारी की दर बढ़कर, 45 साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी है और 6.1 फीसद हो गयी है (राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन)। बेरोजगारी की दर, जो 2018 में 5.9 फीसद थी, 2019 की फरवरी तक बढ़कर 7.1 फीसद पर पहुंच गयी (सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी)। ग्रामीण क्षेत्र में तो हालात और भी

खराब हैं। एनएसएसओ की रिपोर्टों से पता चलता है कि 2011-12 से 2017-18 के बीच, कैजुअल मजदूरी का 3.2 करोड़ लोगों का काम छिना था। इसकी मार ऐसे 1.5 करोड़ परिवारों पर पड़ी थी, जो कैजुअल मजदूरी और खेती, दोनों से होने वाली आय पर गुजर करते थे।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर बढ़ते हमले

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के पिछले भाजपा शासनों में इन अत्याचारों में खासतौर पर बढ़ोतरी हुई थी।

आदिवासियों के विशाल हिस्से को, वनाधिकार कानून के अंतर्गत जमीनों के जो पट्टे मिलने चाहिए थे, उनसे वंचित रखा गया है।

'गुजरात मॉडल' का बहुत ढोल पीटा जाता है, लेकिन उसी गुजरात के उदाहरण से इन बढ़ते हमलों की सचाई को समझा जा सकता है। इस राज्य में पिछले पांच साल में (खुद राज्य विधानसभा के रिकार्ड के अनुसार) अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों में 32 फीसद और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 55 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा

महिलाओं को बढ़ती हिंसा का निशाना बनाया गया है। 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी बढ़ोतरी आंकड़ों में देखने को मिली थी। उसके बाद से इस सरकार ने, इन अपराधों के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े प्रकाशित करना ही बंद करा दिया है।

कुल मिलाकर हमारे समाज का अमानवीयकरण हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति महिलाओं के खिलाफ तथा खासतौर पर छोटी-छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों में होती है। छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की नृशंस वारदातें हो रही हैं।

अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाया

देश में पैदा होने वाली कुल संपदा में, हमारी आबादी के सबसे धनी एक फीसद का हिस्सा, जो 2014 में 49 फीसद था, इन पांच सालों में बढ़कर 73 फीसद हो गया है।

मजदूरों तथा कर्मचारियों की कार्य-दशाओं में हुई भारी गिरावट के साथ ही साथ, पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में असह्य बढ़ोतरी हुई है क्योंकि सरकार ने अपने करों तथा शुल्कों को कम करने से इंकार कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया

इस सरकार द्वारा अपने प्रदर्शन को बढ़ाकर दिखाने के लिए शुरू की गयी नयी जीडीपी शृंखला तक यही बताती है कि 2018-19 की पहली तीन तिमाहियों में जीडीपी 7 फीसद ही रहा था, जो 2013-14 के 8.2 फीसद के स्तर के बाद से, सबसे निचला स्तर है। पहली जीडीपी शृंखला के हिसाब से तो यह सिर्फ 4.7 फीसद ही बैठता है।

पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में, जीडीपी वृद्धि दर और गिरकर 6.6 फीसद रह गयी, जोकि अर्थव्यसस्था के मंदी की ओर खिसक रहे होने का इशारा करता है। यही है भारत के दुनिया की 'सबसे तेजी से बढ़ती' अर्थव्यवस्था होने के मोदी के दावों की हकीकत!

सरकार के सारे लंबे-चौड़े दावों के बावजूद, जीएसटी से राजस्व संग्रह के हिस्से में लगातार गिरावट हुई है और 2017-18 के 7.8 फीसद से घटकर, 2018-19 में यह हिस्सा 5.8 फीसद रह गया है। यह अर्थव्यवस्था की र तार में भारी कमी को दिखाता है।

नोटबंदी और जीएसटी के दुहरे हमले ने, देश की आर्थिक बुनियादों को कमजोर कर दिया है। नोटबंदी से पहले के दौर में विश्व जीडीपी 2.6 की दर से बढ़ रहा था, जबकि भारत में नोटबंदी लागू किए जाने से बाद के दौर में यह 3.1 फीसद की दर से बढ़ रहा था। लेकिन, भारत में नोटबंदी के बाद के दौर में जीडीपी, 7.8 फीसद से गिरकर, 6.8 फीसद रह गया।

जनता की रोजी-रोटी के तबाह किए जाने के चलते घरेलू मांग के स्तर में भारी गिरावट आयी है। इसने विनिर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास को पंगु कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश के अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता, मारुति सुजूकी ने मांग में कमी के चलते, उत्पादन में 27 फीसद कटौती करने का एलान किया है। आठ बुनियादी ढांचागत उद्योगों के विकास दर, 2014 की फरवरी के अपने स्तर के मुकाबले, 2019 की जनवरी तक, 2.9 फीसद नीचे चली गयी थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइपीपी) में 2018 के नवंबर में दयनीय रूप से नीचे चला गया और कोई बढ़ोतरी होने की जगह, उसमें 0.3 फीसद की गिरावट ही दर्ज हुई, जबकि इससे पहले के सात महीनों में औसतन 5.7 फीसद वृद्धि ही हुई थी।

अवमूल्यन के चलते रुपया अपने ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है। जहां 2014 में अमरीकी डालर का भाव 63.19 रु0 चल रहा था, 2019 तक यह भाव बढ़कर 71.76 रु0 पर पहुंच चुका था।

भारत की निर्यात आय में भारी कमी के चलते, देश का भुगतान संतुलन 2014 की फरवरी से 2019 की जनवरी के बीच, पूरे 29 फीसद नीचे खिसक गया है।

इन पांच सालों में बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा यानी भारत के आयातों तथा निर्यातों के मूल्य में बढ़ता हुआ अंतर दर्ज हुआ है। चालू खाता घाटा, जो 2017-18 में जीडीपी के 1.1 फीसद के बराबर था, 2018-19 में 2.9 फीसद हो गया। डालर मूल्य के लिहाज से यह व्यापार घाटे के 6.1 अरब डालर से बढ़कर 19.1 अरब डालर हो जाने को दिखाता है।

इन पांच सालों में कृषि की वृद्धि दर रिकार्ड निचले स्तर पर रही है। कृषि वृद्धि दर 5.1 फीसद से गिरकर 2.7 फीसद रह गयी और 2015 की फरवरी से 2019 की फरवरी के बीच और भी गिरकर, 1.7 फीसद ही रह गयी (सीएसओ)। पिछली चार तिमाहियों में लगातार चौथी बार ऋणात्मक यानी शून्य से कम वृद्धि दर्ज हुई है।

संघीय ढांचे पर हमले

केंद्र-राज्य संबंधों में भारी गिरावट

जीएसटी के लागू होने से राज्यों से राजस्व जुटाने के उनके अधिकार छिन गए हैं।

योजना आयोग के खत्म किए जाने से राज्यों से, अपनी ही आर्थिक योजनाओं व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मंच छिन गया है।

मोदी सरकार लगातार गैर-भाजपा राज्य सरकारों को धारा-356 के तहत भंग करने की धमकियां देती रही है।

इन पांच सालों में केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण असमानतापूर्ण व अन्यायपूर्ण रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

मोदी सरकार की ज मू-कश्मीर नीति सत्यानाशी साबित हुई है। इसने घाटी की जनता का परायापन और बढ़ाया है।

आतंकी वारदातों में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 और 2014-19 की अवधियों के बीच, आतंकवादी हमले की घटनाएं 109 से बढ़कर 626 हो गयी हैं। इन हमलों में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की सं या 139 से बढ़कर 483 हो गयी है। इन घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों की सं या 12 से बढ़कर 210 हो गयी है और युद्धविराम के उल्लंघनों की सं या 563 से बढ़कर, 5596 हो गयी है।

स्थानीय नौजवानों के मिलिटेंट ग्रुपों में शामिल होने में बहुत ही चिंतित करने वाली बढ़ोतरी हुई है। मारे गए स्थानीय मिलिटेंटों की सं या, जो 2014 में 16 ही थी, 2018 में बढ़कर 191 हो गयी।

इस सरकार ने कश्मीर की जनता के साथ किए गए इस वादे के साथ दगा की है कि सभी हितधारकों के साथ राजनीतिक संवाद शुरू किया जाएगा और विश्वास निर्माण के कदम लागू किए जाएंगे।

उरी के आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा पार से आतंकवादी हमले बंद कराने में विफल रही है। इन हमलों का सिलसिला पुलवामा हमले तक जा पहुंचा है।

पाकिस्तान में बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकाने पर वायु सेना के हमले के बाद के दौर में, आतंकवादी हमले जारी रहे हैं तथा और भी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

भाजपा-आरएसएस इस मुद्दे का घृणित तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, जबकि पूरे देश तथा तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का साथ दिया है।

विदेश नीति

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के परित्याग की मु य बातें

विदेश नीति की दिशा को अमरीकी वैश्विक रणनीति के हिसाब से बदला गया है। भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद का कनिष्ठ साझीदार बनाकर रख दिया गया है।

सभी पड़ौसी देशों के साथ बिरादराना संबंधों में गिरावट आयी है।

अमरीका तथा इस्राइल के साथ रक्षा-रिश्तों को गहरा किया गया है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को करीब-करीब छोड़ ही दिया गया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा जिन देशों की संप्रभुता पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें सैन्य दखलंदाजी भी शामिल है, उनके जनगण के साथ भारत की परंपरागत एकजुटता का त्याग कर दिया गया है। वेनेजुएला, इसका ताजातरीन उदाहरण है।

भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के दरवाजे अमरीका के लिए खोल दिए गए हैं और एक बड़े रक्षा साझीदार के तौर पर अमरीका के साथ गठजोड़ किया जा रहा है।

2014 के सभी चुनावी वादों से नंगई से दगा की

इन पांच सालों में भाजपा ने, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने, देश की जनता से किए गए एक-एक वादे को तोड़ा है। हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा यानी अब तक 10 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा; किसानों उनकी कुल उत्पादन लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वादा; काला धन देश में वापस लाने का और हरेक देशवासी के खाते में 15 लाख रु0 जमा कराने का वादा, आदि आदि।

इस सरकार के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए, इस आम चुनाव में मोदी सरकार से, वादे कर के उन्हें तोड़ने के उसके रिकार्ड का हिसाब लिया जाना चाहिए।

फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव, स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जो हमारी धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, संवैधानिक व्यवस्था के भविष्य का फैसला करेगा।

इस संवैधानिक गणतंत्र की हिफाजत करने के लिए, उसे और पु ता करने के लिए और नीतियों की दिशा को एक मूलगामी जनोन्मुखी दिशा में मोड़ने के लिए, यह जरूरी है कि भाजपा और उसके सहयोगियों को हराया जाए।

मतदाताओं से सी पी आइ (एम) की अपील

सी पी आइ (एम) मतदाताओं से अपील करती है:

अ. भाजपायी गठजोड़ को हराओ!

ब. लोकसभा में सी पी आइ (एम) और वामपंथ की ताकत बढ़ाओ!!

स. केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करो!!!

वैकल्पिक नीतियां

यह स्पष्ट है कि हमारे देश और जनता को आर्थिक वृद्धि तथा समग्रता में विकास के एक वैकल्पिक यात्रा पथ की जरूरत है। भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे नीतियों के मौजूदा पैकेज को और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा करने के उसके एजेंडा को ठुकराते हुए, जनहितकारी नीतियों की दिशा में नीतिगत बदलाव के आधार पर ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दरबारी पूंजीवाद के जरिए तथा रफाल लड़ाकू विमान सौदे जैसे घोटालों के जरिए, हमारे संसाधनों की मौजूदा लूट को अगर बंद करा दिया जाए तो, इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं कि देश के हरेक नागरिक को शिक्षा, उ दा स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार तथा उपयुक्त जीवनयापन साधन उपलब्ध कराए जा सकें। बहरहाल, इसके लिए नीतिगत दिशा में मूलगामी बदलाव की जरूरत होगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस तरह के वैकल्पिक नीतिगत मंच की, जिसे लागू करने के लिए सी पी आइ (एम) वचनबद्ध है, मु य बातें इस प्रकार हैं:

मु य बातें

0 धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और संविधान में सन्निहित जनतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत करना।

0 किसानों का इसका अधिकार लागू कराना कि अपनी पैदावार, अपनी कुल उत्पादन लागत से डेढ़ गुने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचें।

0 मजदूरों के लिए कम से कम 18,000 रु0 महीना की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी; मजदूरी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करना।

0 सार्वभौम सार्वजनिक वितरण के जरिए, ज्यादा से ज्याद 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, प्रति परिवार 35 किलोग्राम या प्रतिव्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज का प्रावधान।

0 मु त स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार। निजी बीमा संचालित स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था को खत्म किया जाए। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 5 फीसद के बराबर किया जाए।

0 महिलाओं के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण लागू हो। महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म कराने के लिए चौतरफा कदम उठाए जाएं।

0 शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार हो, जिसमें स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, दोनों शामिल हों। शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 6 फीसद के बराबर किया जाए। शिक्षा का सांप्रदायीकरण रोका जाए और उसका जनतांत्रिक चरित्र सुनिश्चित किया जाए।

0 एक संवैधानिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। बेरोजगारों के लिए बेकारी भत्ते का प्रावधान हो।

0 सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, जो न्यूनतम मजदूरी के कम से कम आधे या 6,000 रु0 महीना में से, जो भी अधिक हो उसके बराबर हो।

0 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जाए और प्रतिरक्षा, ऊर्जा, रेलवे तथा बुनियादी सेवाओं के निजीकरण को पलटा जाए।

0 अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण।

0 धनवानों पर तथा कार्पोरेट मुनाफों पर कर बढ़ाए जाएं। अति-धनिकों पर संपदा कर लगाया जाए और उत्तराधिकार कर लगाया जाए। दीर्घावधि पूंजी लाभ कर बहाल किया जाए।

0 आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाकर चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाए। चुनावी बांड व्यवस्था को निरस्त किया जाए। चुनावी खर्च के लिए, सामग्री के रूप में सरकारी फंडिंग हो।

0